

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023 — वैशाख 29, शक 1945

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक 102/सी.एस.ई.आर.सी./2023.— विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 और 62 सहपठित धारा 181(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस हेतु आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2021 (एतद् पश्चात् प्रमुख विनियम कहा जाएगा) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम, की रचना करता है, नामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

- (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावशील होंगे।

2. कंडिका 2.2 का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 2.2 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः

2.2 ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे

- (i) एकल उत्पादनकर्ता, थोक उपभोक्ता तथा स्वयमेव (केप्टिव) उपयोगकर्ताओं।
बशर्ते ऐसे एकल उत्पादनकर्ता या धारा 63 के अन्तर्गत आने वाले जेनेरेटिंग स्टेशन जो आनुषांगिक सेवाएं भी प्रदान कर रहे हो तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं/या उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु संसूचीकरण, ऊर्जा-मापन या लेखांकन हेतु एस.एल.डी.सी. की सेवाएँ प्राप्त करते हों या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र या ऐसे अन्य किसी उद्देश्यों हेतु जो आयोग के द्वारा समय-समय पर अनिवार्य किये गए हों, को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क एवं प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- (ii) जेनेरेटिंग स्टेशन एवं पारेषण प्रणाली जिनके टैरिफ, केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली संदर्शिका के अनुसरण में प्रतिस्पर्धात्मक बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किये गए हैं एवं अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा अपनायी गयी है।
3. कंडिका 3.10क को जोड़ा जाना — प्रमुख विनियम की कंडिका 3.10 के बाद निम्नलिखित कंडिका 3.10क को जोड़ा जाता है, नामतः:
- 3.10क “विलंबित भुगतान अधिभार की आधार दर” से भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत, जो कि वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसमें वह अवधि निहित है, के साथ-साथ 5 प्रतिशत और निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था जो इसे प्रतिस्थापित करती हो, जिसे केन्द्र सरकार ने राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया हो, से अभिप्रेत है; परन्तु यदि व्यतिक्रम की अवधि दो या अधिक वित्तीय वर्षों के बीच है, विलंब भुगतान अधिभार के आधार दर कि गणना, अलग-अलग वर्षों में आने वाली अवधि के लिए अलग से की जाएगी;
4. कंडिका 3.85 का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 3.85 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः:
- 3.85 इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित रहें, तथापि अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम या अधिनियम की धारा 176/181 के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियम या आयोग द्वारा अन्य अधिसूचित विनियमों में दिया गया है, परन्तु जहां किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संदर्भ में किया गया हो, वहां उस विशिष्ट संदर्भ में प्रयोज्य अर्थ अभिभावी होगा और ऊपर दी गई जेनरिक (मूल) परिभाषा प्रयोज्य न हो सकेगी।
5. कंडिका 15 का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 15 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः —
15. टैरिफ आदेश के प्रति अनुसक्ति (एडहेरेन्स टू टैरिफ आर्डर):
टैरिफ निर्धारण के समस्त आदेश अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक निरंतर प्रवर्तित बने रहेंगे। सामान्यतया कोई टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार, सिवाय आयोग द्वारा अनुमोदित “ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार” (एफ.पी.पी.ए.एस.) सूत्र के आधार पर ईंधन लागत और विद्युत क्रय की वजह से हुए समायोजनों को छोड़कर, संशोधित नहीं किया जाएगा।
6. कंडिका 26.1(क)(vi) का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(क)(vi) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः —
- (vi) 45 दिवस के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज) के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल) जिन्हें मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धताकारक पर परिगणित किया गया है।
7. कंडिका 26.1(क) के परंतुक के पैरा (ग) का संशोधन — कंडिका 26.1(क) के परंतुक के पैरा (ग) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः —
- (ग) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर परिगणित 45 दिवस का विद्युत विक्रय का पूरक क्षमता प्रभार एवं पूरक ऊर्जा प्रभार के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल);
8. कंडिका 26.1(ख)(iii) का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(ख)(iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः —
- (iii) 45 दिवस की स्थिर लागत के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)
9. कंडिका 26.1(ग)(iii) का संशोधन — प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(ग)(iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः —
- (iii) 45 दिवस की स्थिर लागत के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)

10. कंडिका 26.1(ड) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(ड) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –
- 26.1(ड) विद्युत के खुदरा प्रदाय हेतु :
- 15 दिवस के लिये ओ. एंड एम. व्यय, धन
 - विनियम 92.6.2 में विनिर्दिष्ट संधारण एवं सामान्य व्यय का 20 प्रतिशत की दर से संधारण पुर्जे, धन
 - प्रचलित टैरिफ पर, राज्य के भीतर, विद्युत के विक्रय से प्राप्त, 15 दिवस के राजस्व के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)।
11. कंडिका 26.1(च)(iii) का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.1(च)(iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –
- (iii) 45 दिवस के प्रणाली परिचालन प्रभार एवं बाजार प्रचालन प्रभार, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित, के समतुल्य लेनदारी (रिसिवेबल)
12. कंडिका 26.2 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.2 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –
- 26.2 वास्तविकीकरण के समय उत्पादन कंपनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की संगणना हेतु लेनदारी (रिसिवेबल) 45 दिवसों के वास्तविक राजस्व देयक (बिल) के समतुल्य किया जाएगा एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की संगणना हेतु लेनदारी (रिसिवेबल) 15 दिवसों की वास्तविक राजस्व देयक (बिल) के समतुल्य किया जाएगा;
13. कंडिका 26.5 को जोड़ा जाना – प्रमुख विनियम की कंडिका 26.4 के बाद निम्नलिखित कंडिका 26.5 को जोड़ा जाता है, नामतः –
- 26.5. इन विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम के अनुसरण में केंद्रीय या राज्य सरकार, यथा प्रकरण तथैव, के द्वारा धारा 176 या धारा 180 के तहत अधिसूचित अधिभार के भुगतान के संबंध में उत्पादन कंपनी, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा एस.एल.डी.सी. की कार्यशील पूंजी की संगणना हेतु लेनदारी को उतने दिवसों के लिये लगाया जाएगा जितना कि नियमों में नियत हो।
14. कंडिका 29 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 29 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –
29. विलंबित भुगतान पर अधिभार
- 29.1 जहाँ किसी हितग्राही/राज्यांतरिक एकक के द्वारा इन विनियमों के तहत देय प्रभारों के देयकों के भुगतान में देयक के दिनांक से 45 दिवसों से अधिक विलंब किया जाता है वहाँ उत्पादन कंपनी या एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी./प्रणाली परिचालनकर्ता के द्वारा बकाया राशि पर उस अवधि की आधार दर से चूक के पहले महीने के लिये विलंबित भुगतान अधिभार प्रभारित किया जाएगा। वास्तविकीकरण के समय हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किए गए/प्राप्त विलम्बित भुगतान अधिभार को व्यय/राजस्व, यथा प्रकरण तथैव, के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।
- खुदरा उम्मेदाओं से विलंबित भुगतान अधिभार, प्रयोज्य टैरिफ आदेश के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वसूली योग्य होगा।

उत्तरोत्तर मासों में व्यतिक्रम के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर में विलंब के प्रत्येक माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी परंतु विलंब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परंतु वह दर जिस पर विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान किया जाएगा, करार, यदि कोई हो, में विनिर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार की दर से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते आगे यह कि राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियों के अन्तर्गत सक्षम सरकार द्वारा नियम अधिसूचित किए जाने तक, भुगतान प्रतिभूति तंत्र राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा इस तरह के तंत्र का निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशन, राज्य वितरण कंपनी को बिजली आपूर्ति विनियमित नहीं करेंगे।

- 29.2 किसी उत्पादन कंपनी या व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी को उनसे खरीदी गयी विद्युत के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण प्रणाली किसी उपयोक्ता द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सभी भुगतान सबसे पहले विलंब भुगतान अधिभार के प्रति और तत्पश्चात्, सबसे पुराने अतिदेय बिलों से आरम्भ करते हुए, मासिक प्रभारों के प्रति, समायोजित किये जाएंगे।

- 29.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, को बकाया देय तथा किस्तों के संख्या जिनमें, बकाया देय का भुगतान किया जाना है, को लिखित में संप्रेषित करेगा और संप्रेषण इन नियमों के प्रख्यापन से 30 दिवस के भीतर भेजा जाएगा।

परंतु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी मास में, उस मास कि बराबर मासिक किस्त से अधिक का भुगतान भी कर सकता है।

परंतु यह कि सभी यथास्थिति, संबंधित उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को किस्तों का भुगतान, उनके वैयक्तिक बकाया देय के अनुपात पर निर्भर करते हो, यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

- 29.4 विनियम 29.1 में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिभार और संबंधित मामाले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) के अधीन नियत की गई किस्त के अनुसार बकायों के भुगतान हेतु सहमत होता है, और इन किस्तों का समय से भुगतान करता है तो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार भुगतान योग्य नहीं होगा।

- 29.5 विनियम 29.1 के अधीन किसी किस्त के भुगतान के विलंब के मामले में, एलपीएस नियम, 2022 के अधिसूचना की तारीख को सम्पूर्ण बकाया देय पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

- 29.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी या किसी व्यापार कंपनी को इससे विद्युत के क्रय के लिए देय सभी बिल, बिल प्रस्तुत करने के तारीख और समय के संबंध में समय अंकित होंगे और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया भुगतान पहले सबसे पुराने बिल के लिए और फिर दूसरे सबसे पुराने बिल के लिए और फिर इसी क्रम में समायोजित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की जब तक सभी पुराने बिलों का भुगतान न कर दिया गया हो, तब तक किसी बिल के भुगतान को समायोजित नहीं किया जाएगा।

परंतु विलंब भुगतान अधिभार के लिए हुई समायोजन विनियम 29.2 में यथाविनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

- 29.7 यदि विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित कोई प्रावधान और कार्यप्रणाली जो एलपीएस नियम 2022 में उपलब्ध है किन्तु इस विनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं तो ऐसे प्रावधान एलपीएस नियम 2022 के अनुसार होंगे।
आगे यह कि यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 या धारा 180 के अन्तर्गत प्रचलित नियमों में संशोधन करती है या कोई नया नियम बनाती है, जैसा भी मामला हो, विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, विलंब भुगतान अधिभार से संबंधित ऐसे नियम के प्रावधान लागू होंगे।
15. कंडिका 37.1 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 37.1 की टीप में बिन्दु 4 के बाद बिन्दु 5 को प्रविष्ट किया जाता है, नामतः –
5. केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्पादन कंपनी पर लागू होगा।
परन्तु यह कि उस परिस्थिति में जब अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के अवधारण के पश्चात् किसी विधि के संशोधन या निरसन की वजह से विधि में परिवर्तन हुआ हो, तब उत्पादन कंपनी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत प्रभावित राशि (अचर/आवर्ती) की वसूली हेतु प्रपत्रों एवं प्रक्रियाओं के एक बार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। नियमों के अनुसरण में परिवर्ती वसूली तदनुसार की जाएगी।
16. कंडिका 45.3क को जोड़ा जाना – प्रमुख विनियम की कंडिका 45.3 के बाद कंडिका 45.3क को जोड़ा जाता है, नामतः –
- 45.3क जहां किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ईंधन की कमी हो जाती है वहां उत्पादन कंपनी अधिकतम मांग के घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट का प्रदाय प्रस्तावित कर सकती है, जिससे ऑफ पीक घंटों के दौरान ईंधन की बचत हो सके। उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र के लिए, हितग्राहियों के परामर्श से, एक व्यावहारिक दिवस पूर्व, अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे इसकी मेगावाट और विद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ऐसी स्थिति में औसत घोषित क्षमता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची में अधिकतम पीक अवर एक्स पॉवर प्लाण्ट मेगावाट के समतुल्य लिया जाएगा।
17. कंडिका 45.11 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 45.11 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –
- 45.11 प्राथमिक ईंधन मूल्य में मासिक वृद्धि की वसूली इन विनियमों के विनियम 93 में दर्शाए ईंधन लागत समायोजन प्रणाली के अनुसार की जाएगी।
18. कंडिका 72 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 72 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –
72. पारेषण अनुज्ञापिधारी इस विनियम के अध्याय – 2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।
परन्तु यह कि समस्त राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली जिनकी लागत सीमा रु. 250 करोड़ से अधिक हो तथा वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकसित किये जाएंगे तथा उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अन्तर्गत आयोग के द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा

जारी सुसंगत संदर्शिका (तथा उनके संशोधनों) के अनुसरण में विवेकपूर्ण परीक्षण के उपरांत अपनाया जाएगा।

सम्पूर्ण राज्यांतरिक स्वतंत्र पारेषण प्रणाली, उर्ध्वधारा/अधोधारा परियोजनाओं सहित, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विकसित करने हेतु बोलियाँ आमंत्रित करने के लिए एकल परियोजना के रूप में गढ़ी जाएंगी।

उस परिस्थिति में जहाँ राज्य सरकार/एस.टी.यू. कोई राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली जो लागत सीमा से ऊपर है, किसी विशिष्ट कारणवश जैसे परियोजना रणनीतिक महत्त्व की है या दुष्कर प्रकृति की है या परियोजना स्वामित्व अथवा गठजोड़ का मुद्दा खड़ा कर सकती है, लागत धन प्रकार से विकसित करने की इच्छुक हैं, तब राज्य सरकार ऐसी रणनीतिक महत्त्व और दुष्कर प्रकृति की परियोजनाओं का निर्णय लेगी तथा राज्य सरकार/एस.टी.यू. इस बाबत आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

19. कंडिका 73.1 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 73.1 की टीप के बिन्दु 4 के बाद बिंदु 5 को प्रविष्ट किया जाता है, नामतः –

5 केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होगा।

परन्तु यह कि उस परिस्थिति में जब अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के अवधारण के पश्चात् किसी विधि के संशोधन या निरसन की वजह से विधि में परिवर्तन हुआ हो, तब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित पक्षकार की हैसियत से विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत प्रभावित राशि (अचर/आवर्ती) की वसूली हेतु प्रपत्रों एवं प्रक्रियाओं के एक बार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे। नियमों के अनुसरण में परिवर्ती वसूली तदनुसार की जाएगी।

20. कंडिका 92.4.4 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 92.4.4 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –

92.4.4 विद्युत क्रय की लागत में मासिक बढ़त, इस विनियम के विनियम 93 में वर्णित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफ.पी.पी.ए.एस.) क्रियाविधि के अनुसार, वसूली-योग्य होगी।

21. कंडिका 93 का संशोधन – प्रमुख विनियम की कंडिका 93 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नामतः –

93. ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफ.पी.पी.ए.एस.)

93.1 $n^{\text{वै}}$ माह के वास्तविक टैरिफ की तुलना में टैरिफ आदेश में अनुमोदित $n^{\text{वै}}$ माह के टैरिफ में विचलन के हिसाब की रकम (कोयले की पहुँच लागत तथा विवेकपूर्ण परीक्षण इत्यादि के उपरांत प्रतिष्ठित तृतीय पक्षकार एजेंसी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र/जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरिफिक मान में विचलन के फलस्वरूप) उन उत्पादन स्टेशनों के द्वारा जो राज्य में स्थित हैं तथा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करते हैं, मासिक आधार पर निश्चित किये जाएंगे तथा $(n+2)^{\text{वै}}$ माह के नियमित मासिक देयकों के द्वारा पंक्ति मद नामतः ईंधन एवं अन्य व्यय के बतौर वसूल किये जाएंगे।

उदाहरण :- वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बिजली की आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनी अप्रैल महीने का ईंधन लागत समायोजन (एफ.सी.ए.), मई महीने के दौरान आपूर्ति की

गई बिजली के बिल जो कि जून महीने में जारी किया जाएगा, में एक पंक्ति मद के रूप में जुटाएगी।

- 93.2 उत्पादन कंपनी द्वारा अपने प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए प्रत्येक माह हेतु एफ.सी. ए. पृथकतः परिगणित किया जाएगा। किसी माह के लिए एफ.सी.ए. की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

FCA, (रूप्यों में) = माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस) X मासिक ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन, (ई.सी.आर.) मासिक ऊर्जा प्रभार में अंतर = ECR (T) - ECR (M)

जहां,

ECR (T) = मासिक ऊर्जा प्रभार, टैरिफ ओदश में उस विशिष्ट संयंत्र के लिए विनिर्दिष्ट

ECR(M) = विशिष्ट संयंत्र हेतु विशिष्ट माह के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित ECR

ECR (M) = $\{(GHR - SFC \times CVSF) \times LPPF / CVPF\} \times 100 / (100 - AUX)$

जहां,

AUX = मानकीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = प्राथमिक ईंधन का सकल कैलॉरिफिक मान प्राप्ति के रूप में, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में,

CVSF = द्वितीयक ईंधन का कैलॉरिफिक मान, किलो कैलोरी प्रति मिली लीटर में, टैरिफ आदेश में यथाविचारित

GHR = मानकीय सकल स्थानक ऊष्मा दर, (नॉर्मेटिवग्रास स्टेशन हीट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अवर में टैरिफ आदेश में यथा अनुमत

LPPF = प्राथमिक ईंधन की वास्तविक भारांकित औसत पहुँच-कीमत, प्रति किलोग्राम, रूप्यों में

SFC = मानकीय विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिली लीटर प्रतिकिलोवाट अवर में

उत्पादन कंपनी, मानकीय जी.एस.एच.आर., मानकीय सहायक खपत, मानकीय विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, कोयले की भारांकित औसत जी.सी.व्ही. प्राप्ति के रूप में और प्राथमिक ईंधन की वास्तविक भारांकित औसत पहुँच-कीमत के आधार पर ई.सी. आर. तैयार करेगा।

परन्तु यह भी कि यदि उत्पादन कंपनी के द्वारा वास्तविकीकरण के वक्त कोई अतिरिक्त दावा दायर किया जाता है, तो वह विवेकपूर्ण परीक्षण के अध्यधीन लिखित में अभिलेखित कारणों से पुष्ट होगा।

परन्तु यह कि उत्पादन कंपनी हेतु अनियंत्रणीय कारणों से, जिसमें किसी माह की समस्त प्रमाणित जाँच रिपोर्ट की अनुपलब्धता भी शामिल है, उत्पादन कंपनी उस माह के लिये प्राविधिक ईंधन एवं अन्य व्यय प्रभार जारी करेगी, जिस माह में उक्त अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होगी उस से अगले माह में अंतिम (फायनल) देयक तैयार किया जाएगा तथा अंतर की रकम की मांग की जाएगी।

कोयला आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों द्वारा ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के आंशिक या पूर्ण उपयोग के मामले में, उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों द्वारा उनके बिजली खरीद समझौते में सहमति के अलावा या ईसीआर के निर्धारण के लिए संबंधित टैरिफ आदेश में विचार के अनुसार सम्मिश्रण के माध्यम से ईंधन की कमी या किफायती संचालन के अनुकूलन, ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग की अनुमति उत्पादन स्टेशन को दी जाएगी: बशर्ते कि जहां ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर ईंधन की भारित औसत कीमत, आयोग द्वारा अनुमोदित आधार ऊर्जा प्रभार दर के 20% से अधिक हो, उस स्थिति में, हितग्राही के साथ पूर्व परामर्श

और आयोग के अनुमोदन के बाद ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर विचार किया जाएगा।

- 93.3 इन नियमों के लिए "ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार" (एफ.पी.पी.ए.एस.) का अर्थ आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और पारेषण प्रभारों में परिवर्तन के कारण, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई, विद्युत की लागत में वृद्धि से है।

बशर्ते कि किसी महीने के बिजली बिक्री बिल के साथ उत्पादक कंपनी/स्टेशन से प्राप्त एफसीए बिल को वितरण कंपनी द्वारा उसी महीने की बिजली खरीद लागत माना जाएगा।

उदाहरण के लिए:—यदि कोई वितरण कंपनी किसी उत्पादन कंपनी से दीर्घकालिक आधार पर बिजली खरीद रही है और आयोग द्वारा विस्तृत प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन कंपनी 'अप्रैल' महीने के ऊर्जा बिल के साथ पूर्व अवधि के लिए ईंधन लागत समायोजन का दावा करती है। तब एफसीपीएएस की गणना के उद्देश्य से, वितरण कंपनी ऐसे एफसीए को केवल 'अप्रैल' महीने की बिजली खरीद लागत के हिस्से के रूप में मानेगी।

- 93.4 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की स्वतः विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना, मासिक आधार पर, संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित विनियम के अनुसार, ट्रू-अप के अध्यक्षीन, वार्षिक आधार पर, जैसा कि आयोग द्वारा तय किए गए अनुसार, संगणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को बिल भेजा जाएगा:

परन्तु इन नियमों के अनुसार मासिक बिलिंग के लिए स्वचालित पास-थ्रू को समायोजित किया जाएगा।

- 93.5 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय की लागत में, वास्तविक भिन्नता और $n^{\text{वै}}$ माह के दौरान खरीदी गई विद्युत के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों के आधार पर $(n+2)^{\text{वै}}$ माह में संगणना की जाएगी और प्रभारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में परिवर्तनों के कारण ईंधन और विद्युत क्रय अधिभार की संगणना की जाएगी और उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में अप्रैल माह की ऊर्जा प्रभार पर बिल किया जायेगा।

परन्तु यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारक, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के अलावा, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है, तो इसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण लागत की वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू-अप के दौरान निर्धारित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा।

- 93.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह निर्णय ले सकेगा कि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार या उसका एक भाग, उपभोक्ताओं को किसी टैरिफ आघात से बचाने के लिए अगले माह तक आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने की अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा, यदि किसी बिलिंग माह के लिए कुल ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, जिसमें पिछले माह में ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को किसी प्रकार आगे बढ़ाए जाने सहित, अनुमोदित टैरिफ के परिवर्तनीय घटक के 20 प्रतिशत से अधिक हो।

- 93.7 आगे बढ़ाए गए अधिभार को एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पहले, जो भी पहले हो वसूला जाएगा तथा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूली गई धनराशि को पहले ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सबसे पहले आगे बढ़ाए गए भाग के अनुसार संगणित किया जाएगा और इसका अनुसरण बाद के माह में भी किया जाएगा।
- 93.8 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाए जाने के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पॉइंट बेस्ट लेंडिंग रेट जमा एक सौ पचास बेसिस पॉइंट की अनुमति दी जाएगी जब तक कि इसे टैरिफ के माध्य से वसूला नहीं जाता और इस वहनीय लागत का ट्रू-अप विचाराधीन वर्ष में किया जाएगा।
- 93.9 ईंधन की मात्रा और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के आधार पर, स्वचालित पास-थ्रू को इस तरह से समायोजित किया जाएगा कि,
- (i) यदि ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार $\leq 5\%$ है, तो संगणित ईंधन की वसूली योग्य लागत का 100% तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र का प्रयोग करते हुए स्वतः वसूला जाएगा।
 - (ii) यदि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार $> 5\%$, 5% ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार उपरोक्त 93.9(i) के अनुसार स्वचालित रूप से वसूला जाएगा। शेष ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का 90% को सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूला जा सकेगा और राज्य आयोग द्वारा ट्रू-अप के दौरान अनुमोदन के बाद अंतर संबंधी दावा वसूला जा सकेगा।
- 93.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूले गए राजस्व को, विचाराधीन वर्ष के लिए बाद में वार्षिक राजस्व आवश्यकता के ट्रू-अप के साथ ट्रू-अप किया जाएगा।
- 93.11 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के निमित्त वर्ष के लिए वसूले गए अतिरिक्त/अनतिरिक्त राजस्व के मामले में, इसे अनुज्ञप्तिधारकों में ट्रू-अप के समय इसकी वहनीय लागत के साथ वसूला जाएगा।
- 93.12 वितरण अनुज्ञप्तिधारक, निर्धारित प्रारूपों में, किए गए खर्च और वसूले गए ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के बीच भिन्नता के विवरण प्रस्तुत करेगा, और विस्तृत संगणनाएं और सहायक दस्तावेज, जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित होंगी, सामान्य टैरिफ के ट्रू-अप के दौरान प्रस्तुत करेगा।
- 93.13 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार तंत्र के सुचारु कार्यान्वयन और इसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारक संबंधी बिलिंग प्रणाली को उक्त को ध्यान में रखते हुए अद्यतित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाएगी कि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता के बावजूद इन्टरऑपरेबिलिटी या यथा-उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली मौजूद है।
- 93.14 अनुज्ञप्तिधारक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना तथा ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (स्वचालित एवं अनुमोदित भागों के लिए अलग-अलग) की वसूली सहित सभी विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और उसे एक समर्पित वेब पते के माध्यम से संगणित करेगा।

93.15 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना:

सूत्र:

$$n^{\text{व}} \text{ माह के लिए मासिक एफपीपीएस (\%)} = \frac{(ए-बी)*सी + (डी-ई)}{\{जेड*(1 - वितरण हानि \% / 100)\} * एबीआर}$$

जहां,

(n+2)^व माह का अर्थ वह माह होता है जिसमें ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार n^व माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए टैरिफ में बदलाव के कारण लगाया जाता है

ए सभी स्रोतों से n^व माह (केडब्ल्यूएच में) में खरीदी गई कुल युनिटें हैं जिनमें दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पावधि विद्युत खरीद (वितरण अनुज्ञापिधारकों को जारी किए गए बिलों से ली जाएगी) शामिल हैं

बी n^व माह में सभी स्रोतों से विद्युत की थोक बिक्री है। (केडब्ल्यूएच में) = (जिसे प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी किए गए अनंतिम खातों से लिया जाना है एवं इसे एसएलडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा)

सी वृद्धिशील औसत विद्युत क्रय लागत = n^व माह में सभी स्रोतों से वास्तविक औसत विद्युत क्रय लागत जल प्रभार, सांविधिक कर, ड्यूटी, उपकर सहित (पीपीसी) (रु/केडब्ल्यूएच) (संगणित) - सभी स्रोतों से अनुमानित औसत विद्युत क्रय लागत (पीपीसी) (रु/केडब्ल्यूएच) - (टैरिफ ऑर्डर से) है

डी n^व माह में वास्तविक अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारषेण प्रभार, (ट्रांसको से डिस्कोम द्वारा बिलों से) (रुपये में), हैं

ई n^व माह के लिए पारषेण प्रभारों की मूल लागत = (अनुमोदित पारषेण प्रभार/12) (रुपये में) है

जेड [(n^व माह में राज्य के बाहर सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तविक विद्युत (केडब्ल्यूएच में) * (1 - % में अंतर - राज्यीय पारषेण हानियां/100) + राज्य के भीतर सभी स्रोतों से खरीदी गई विद्युत (केडब्ल्यूएच में) - बी] * (1 - % में अंतरा-राज्यीय हानियां)/100 केडब्ल्यूएच में

एबीआर = वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (रुपये/केडब्ल्यूएच में टैरिफ आदेश से लिया जाएगा)

वितरण हानियां (% में) = लक्षित वितरण हानियाँ (टैरिफ आदेश से)

अंतरा-राज्यीय हानियां (% में) = टैरिफ आदेश के अनुसार

93.16 विद्युत क्रय लागत में विचलन निपटान तंत्र के परिणाम स्वरूप कोई भी प्रभार शामिल नहीं होंगे।

93.17 अन्य प्रभारों जिनमें सहायक सेवाएं तथा सिक्योरिटी कंसट्रेंड इकोनोमिक डिस्पैच शामिल हैं, को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में शामिल नहीं किया जाएगा और राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित टू-अप के माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./ -

(सुधीर कुमार काले)

उप-सचिव.

Raipur, the 10th May 2023

NOTIFICATION

No. 102/CSERC/2023.— In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission hereby makes following regulations, to amend Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:

1. Short title and commencement:

- (1) These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) (First Amendment) Regulations, 2023.
- (2) These Regulations shall be effective from 1st April, 2023.

2. Amendment of Clause 2.2 -Clause 2.2 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

2.2 This Regulation will not apply to

- (i) Stand-alone generators, bulk consumers and captive users.

Provided, that the stand-alone generators or any generating stations covered under Section 63 and excusing as Ancillary services who avail services of SLDC for scheduling, energy metering or accounting for the purpose of supply of its power to a licensee and/or consumers or Renewable Energy Certificates or any other such purposes as may be mandated by the Commission from time to time shall be required to pay fee & charges as specified under this Regulation.

- (ii) Generating Stations and Transmission System whose tariff has been discovered through a transparent process of competitive bidding in accordance with the competitive bidding guidelines notified by the Central Government and adopted by the Commission under Section 63 of the Act after prudence check.

3. Addition of Clause 3.10A – The following Clause shall be added after Clause 3.10 of the Principal Regulations namely:

3.10A "base rate of Late Payment Surcharge" means the marginal cost of funds based on lending rate for one year of the State Bank of India, as applicable on the 1st April of the financial year in which the period lies, plus five percent

and in the absence of marginal cost of funds based lending rate, any other arrangement that substitutes it, which the Central Government may, by notification, in the Official Gazette, specify:

Provided that if the period of default lies in two or more financial years, the base rate of Late Payment Surcharge shall be calculated separately for the periods falling in different years ;

4. Amendment of Clause 3.85 -Clause 3.85 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

3.85 The words and expressions used in the Regulation and not defined herein but defined in the Act or Rules notified by the Central / State Government under Section 176 / 181 of the Act or other Regulations notified by the Commission shall have the meaning assigned to them under the Act, Rules and other Regulations notified by the Commission, provided that when a word or phrase is used by the Commission in a specific context, the meaning applicable in that specific context, shall prevail and the generic definition given above may not be applicable.

5. Amendment of Clause 15 – Clause 15 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

15. ADHERENCE TO TARIFF ORDER

All tariff orders passed under this Regulation shall be in force till issue of next tariff order. No tariff or part of any tariff may be ordinarily amended, more frequently than once in any financial year, except adjustment on account of fuel cost and power purchase based on Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) formula approved by the Commission.

6. Amendment of Clause 26.1(a)(vi) –Clause 26.1(a)(vi) of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

(vi) Receivables equivalent to 45 days of capacity charges and energy charges for sale of electricity calculated on the normative annual plant availability factor.

7. Amendment of para (c) of proviso of Clause 26.1(a) – Para (c) of proviso of Clause 26.1(a) of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

(c) Receivables equivalent to 45 days of supplementary capacity charges and Supplementary energy charges for sale of electricity calculated on the normative annual plant availability factor.

8. Amendment of Clause 26.1(b)(iii) – Clause 26.1(b)(iii) of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

(iii) Receivables equivalent to 45 days of fixed cost.

9. Amendment of Clause 26.1(c)(iii) – Clause 26.1(c)(iii) of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

(iii) Receivables equivalent to 45 days of fixed cost.

10. Amendment of Clause 26.1(e) - Clause 26.1(e) of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

26.1(e) For Retail Supply of Electricity:

- i. O&M expenses for 15 days; plus
- ii. Maintenance spares @ 20% of Maintenance and General expenses specified in Regulation 92.6.2; plus
- iii. Receivables equivalent to 15 days of the revenue from sale of electricity at the prevailing tariffs within state;

11. Amendment of Clause 26.1(f)(iii) - Clause 26.1(f)(iii) of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

- (iii) Receivables equivalent to 45 days of system operation charges and market operation charges as approved by the Commission.

12. Amendment of Clause 26.2 - Clause 26.2 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

26.2 At the time of True-Up, the receivables for the computation of working capital requirement of the generating company, STU/transmission licensee and SLDC will be determined equivalent to 45 days of actual revenue billed and the receivables for the computation of working capital requirement of the distribution licensee will be determined equivalent to 15 days of actual revenue billed.

13. Addition of Clause 26.4 - The following Clause shall be added after Clause 26.4 of the Principal Regulations namely:

26.5 Notwithstanding the provisions of these Regulations, the receivables to be considered for computation of working capital for the generating company, STU/transmission licensee and SLDC, shall be considered for such number of days as may be prescribed in the Rules, related to payment of surcharge, notified by the Central or State Government under Section 176 or Section 180, as the case may be, in accordance with the Act.

14. Amendment of Clause 29 - Clause 29 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

29. LATE PAYMENT SURCHARGE

29.1 In case the payment of any bill for charges payable under this Regulation is delayed by a beneficiary/ intra-state entity beyond a period of 45 days from the date of billing, a late payment surcharge at the base rate for the period for the first month of default on outstanding amount, shall be levied by the generating company or the STU/transmission licensee or the SLDC/ system operator. At the time of true-up, the late payment surcharge paid received by the beneficiary/licensee shall not be considered as an expense/ revenue, as the case may be.

Late Payment Surcharge from retail consumers shall be recoverable as per the relevant provisions of applicable Tariff Order.

The rate of Late Payment Surcharge for the successive months of default shall increase by 0.5 percent for every month of delay, provided that the Late Payment Surcharge shall not be more than three percent higher than the base rate at any time.

Provided that the rate, at which Late Payment Surcharge shall be payable, shall not be higher than the rate of Late Payment Surcharge specified in the agreement, if any.

Provided further that unless otherwise notified by the competent Government under the rule making powers conferred by the Act for the state-owned generating stations, the payment security mechanism shall be as decided by the State Government and till such mechanism is decided by the State Government, unless otherwise directed to, the state-owned generating stations shall not regulate power supply to the State Distribution Company.

29.2 All payments by a Distribution Licensee to a Generating Company for power procured from it or by a user of a transmission system to a Transmission Licensee shall be first adjusted towards Late Payment Surcharge and thereafter, towards monthly charges, starting from the longest overdue bill.

29.3 In case the Distribution Licensee has communicated, in writing, to the Generating Company or Transmission Licensee, as the case may be, the outstanding dues and number of installments in which, the outstanding dues would be paid, within thirty days of the notification of the Late Payment Surcharge Rules, 2022, the following conditions shall be applicable:

Provided that the Distribution Licensee may make payment in a month more than the equated monthly installment for the month;

Provided that the payment of installment shall be done to all the concerned Generating Companies and Transmission Licensees, as the case may be, on pro-rata basis, depending upon the proportion of their individual outstanding dues.

29.4 Notwithstanding anything contained in Regulation 29.1, if the Distribution Licensee agrees to payment of the arrears dues as per the installment fixed under the Late Payment Surcharge Rules, 2022 (LPS Rules 2022), and makes timely payment of these installments, then the Late Payment Surcharge shall not be payable on the outstanding dues.

29.5 In case of delay in payment of an installment under Regulation 29.1, Late Payment surcharge shall be payable on the entire outstanding dues as on the date of notification of the LPS Rules, 2022.

29.6 All the bills payable by a Distribution Licensee to a Generating Company or a Transmission Company shall be time tagged with respect to the date and time of submission of the bill and the payment made by the Distribution Licensee shall be adjusted first against the oldest bill and then to the second oldest bill and so on, so as to ensure that payment against a bill is not adjusted unless and until all bills older than it have been paid for:

Provided that any adjustment towards Late Payment Surcharge shall be done in the manner as specified in Regulation 29.2.

29.7 The provisions and methodologies not specified in the Regulation shall be in accordance to LPS Rules 2022.

Further, if the Central Government or the State Government amend the prevailing rule or makes any new rule under the Section 176 or Section 180, as the case may be, of the Electricity Act 2003 related to late payment surcharge, to the extent, scope and applicability prescribed under such rules, notwithstanding the provisions of the regulations, the provisions of such rule shall prevail.

15. Amendment of Clause 37.1 – Addition of point 5 after point 4 of NOTE in Clause 37.1 of the Principal Regulations namely: -

5. The Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Central Government as amended from time to time, shall be applicable to generating company.

Provided that in case of any event in change of law arising out of amendment or repeal of any law made after the determination of tariff under Section 62 or 63 of the Act the generating company, being the affected party shall be at liberty to approach the Commission for one time approval of formats and procedures for invoking recovery of the impacted amount (fixed / recurring amount) under the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 as may be amended from time to time. The subsequent recovery shall be in accordance to the rules.

16. Addition of Clause 45.3 A – The following Clause shall be added after Clause 45.3 of the Principal Regulations namely:

- 45.3A In case of fuel shortage in a thermal generating station, the generating company supplying total power to distribution licensee of the State, may propose to deliver a higher MW during peak-load hours by saving fuel during off-peak hours. The State Load Despatch Centre may then specify a pragmatic day-ahead schedule for the generating station to optimally utilize its MW and energy capability, in consultation with the beneficiaries. DCi in such an event shall be taken to be equal to the maximum peak-hour ex- power plant MW schedule specified by the State Load Despatch Centre for that day.

17. Amendment of Clause 45.11 - Clause 45.11 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

- 45.11 The monthly variation in fuel and other expenses shall be recoverable as per the mechanism detailed in Regulation 93 of this Regulation.

18. Amendment of Clause 72 - Clause 72 of the Principal Regulation shall be substituted namely: -

72. The transmission licensee shall submit a capital investment plan in the manner specified in Chapter-2 of this Regulation.

Provided that all new Intra-State transmission system costing above a threshold limit Rs. 250 Crores and meeting other conditions as laid out below shall be developed through Tariff Based Competitive Bidding and shall be adopted by the Commission under section 63 of the Electricity Act' 2003 after prudence check in accordance with the relevant Guidelines (and its amendments) issued by the Ministry of Power, Government of India.

The entire Intra-State independent transmission system including any upstream/downstream project shall be designed as single project for inviting bids for development of project through Tariff Based Competitive Bidding.

In case the State Govt/STU intends to develop any Intra-State Transmission System above the threshold limit through cost plus approach due to some specific reasons such as project is of strategic importance or critical nature or project may lead to ownership or interface issues, State Govt. shall decide any such projects of strategic importance or critical in nature and the State Govt/STU shall obtain prior approval of the Commission for the same.

19. Amendment of Clause 73.1 – Addition of point 5 after point 4 of NOTE in Clause 73.1 of the Principal Regulations namely: -

5. The Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 notified by Central Government as amended from time to time, shall be applicable to transmission licensee.

Provided that in case of any event in change of law arising out of amendment or repeal of any law made after the determination of tariff under Section 62 or 63 of the Act the transmission licensee, being the affected party shall be at liberty to approach the Commission for one time approval of formats and procedures for invoking recovery of the impacted amount (fixed / recurring amount) under the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021 as may be amended from time to time. The subsequent recovery shall be in accordance to the rules.

20. Amendment of Clause 92.4.4 - Clause 92.4.4 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

- 92.4.4 The monthly Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) shall be recoverable as per the mechanism detailed in Regulation 93 of this Regulation.

21. Amendment of Clause 93 – Clause 93 of the Principal Regulations shall be substituted namely: -

93. FUEL AND POWER PURCHASE ADJUSTMENT SURCHARGE (FPPAS)

- 93.1 Amount on account of variation in actual Energy Charge of n^{th} month (due to variation in the Landed price of Coal and Gross Calorific Value of primary fuel on the basis of certificate / test report issued by reputed third party agency after prudence check etc.) vis-à-vis Energy Charge of n^{th} month as approved in tariff order shall be determined on monthly basis by generating stations which are situated within the State and supplying power to distribution licensee of the State and the same shall be recovered through regular monthly bills issued in $(n+2)^{\text{th}}$ month as a line item namely fuel and other expenses.

Example –A generating company supplying power to distribution licensee shall raise the FCA for the month of April as a line item in the regular monthly bill in the month of June, for the power supplied during month of May.

- 93.2 The FCA shall be calculated by the generating company for each of its thermal stations separately for each month. The FCA for a month shall be calculated as under:

FCA (in Rs.) = Scheduled energy (ex-bus) for the month X difference in monthly Energy Charge Rate (ECR),

Difference in monthly ECR = ECR (T) - ECR (M)

Where,

ECR (T): ECR specified for the particular plant in the tariff order.

ECR (M) = Computed ECR for the particular plant for the particular month as per formula given below.

ECR(M): $\{(GHR-SFC \times CVSF) \times LPPF/CVPF\} \times 100/(100-AUX)$

Where,

AUX = Normative auxiliary energy consumption in percentage.

CVPF: Gross calorific value of primary fuel as received in kCal per kg

CVSF = Calorific value of secondary fuel as considered in the tariff order, in kCal per ml.

GHR: Normative Gross station heat rate allowed in the Tariff order, in kCal per kWh.

LPPF = Actual Weighted average landed price of primary fuel, in Rupees per kg

SFC: Normative Specific fuel oil consumption, in ml per kWh.

The generating company shall work out the ECR on the basis of normative GSHR, normative auxiliary consumption, normative specific secondary fuel oil consumption, weighted average GCV of the coal as received and secondary fuel oil as indicated in the tariff order and actual landed price of the primary fuel (LPPF).

Provided further that if any additional claim is raised by the generating company at the time of true up the same shall have to be supported by reasons recorded in writing and shall be subject to prudence check.

Provided that for the reasons uncontrollable for the generating company, including but not limited to non-availability of the all the certified test reports for a month, generating company shall issue provisional fuel and other expenses charge for that month based on the available reports, the final bill shall be prepared and differential amount shall be claimed in the month next to the month in which last of such report is received.

In case of part or full use of alternative source of fuel supply by coal based thermal generating stations other than as agreed by the generating company and beneficiaries in their power purchase agreement or as considered in the respective Tariff Order for determination of the ECR, on account of shortage of fuel or optimization of economical operation through blending, the use of alternative source of fuel supply shall be permitted to generating station: Provided that where the energy charge rate based on weighted average price of fuel upon use of alternative source of fuel supply exceeds 20% of base

energy charge rate as approved by the Commission, in that event, use of alternative source of fuel supply shall be considered after prior consultation with beneficiary and approval of the Commission.

- 93.3 Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) means the increase in cost of power, supplied to consumers, due to change in fuel cost, power purchase cost and transmission charges with reference to cost of supply approved by the Commission.

Provided that FCA bill received from a generating company / station along with the power sale bill for a particular month shall be considered as power purchase cost of the distribution company for that month only.

For Example – If a distribution company is purchasing power from a generating company on long term basis and the generating company based on the procedure detailed by the Commission claims Fuel Cost Adjustment for the prior period along with the energy bill for the month of 'April', then for the purpose of the computation of FPPAS, the distribution company shall consider such FCA as part of power purchase cost of the month of 'April' only.

- 93.4 Fuel and power purchase adjustment surcharge shall be calculated and billed to consumers, automatically, without going through regulatory approval process, on a monthly basis, according to the formula, prescribed by the Commission, subject to true up, on an annual basis, as decided by the Commission:

Provided that the automatic pass through shall be adjusted for monthly billing in accordance with this Regulation.

- 93.5 Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge shall be computed and charged by the distribution licensee, in $(n+2)^{th}$ month, on the basis of actual variation, in cost of fuel and power purchase and Inter-state Transmission Charges for the power procured during the n^{th} month and shall be recoverable from the consumers on their energy charge of n^{th} month. For example, the fuel and power purchase adjustment surcharge on account of changes in tariff for power supplied during the month of April of any financial year shall be computed and billed in the month of June of the same financial year on the energy charge of April month:

Provided that in case the distribution licensee fails to compute and charge fuel and power purchase adjustment surcharge within this time line, except in case of any force majeure condition, its right for recovery of costs on account of fuel and power purchase adjustment surcharge shall be forfeited and, in such cases, the right to recovery the fuel and power purchase adjustment surcharge determined during true-up shall also be forfeited.

- 93.6 The distribution licensee may decide, fuel and power purchase adjustment surcharge or a part thereof, to be carried forward to the subsequent month in order to avoid any tariff shock to consumers, but the carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge shall not exceed a maximum duration of two months and such carry forward shall only be applicable, if the total fuel and power purchase adjustment surcharge for a Billing Month, including any carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge over the

- previous month exceeds twenty per cent of variable component of approved tariff.
- 93.7 The carry forward shall be recovered within one year or before the next tariff cycle whichever is earlier and the money recovered through fuel and power purchase adjustment surcharge shall first be accounted towards the oldest carry forward portion of the fuel and power purchase adjustment surcharge followed by the subsequent month.
- 93.8 In case of carry forward of fuel and power purchase adjustment surcharge, the carrying cost at the rate of State Bank of India Marginal cost of Funds-based lending Rate plus one hundred and fifty basis points shall be allowed till the same is recovered through tariff and this carrying cost shall be trued up in the year under consideration.
- 93.9 Depending upon quantum of fuel and power purchase adjustment surcharge, the automatic pass through shall be adjusted in such a manner that,
- (i) If fuel and power purchase adjustment surcharge $\leq 5\%$ of the ABR, 100% cost recoverable of computed fuel and power purchase adjustment surcharge by distribution licensee shall be levied automatically using the formula.
 - (ii) If fuel and power purchase adjustment surcharge $> 5\%$ of the ABR, 5% fuel and power purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically as per 93.9(i) above. 90% of the balance fuel and power purchase adjustment surcharge shall be recoverable automatically using the formula and the differential claim shall be recoverable after approval by the Commission during true up.
- 93.10 The revenue recovered on account of pass through fuel and power purchase adjustment surcharge by the distribution licensee, shall be trued up along with true up of the ARR.
- 93.11 In case of excess / under recovery for the year against the fuel and power purchase adjustment surcharge, the same shall be recovered from/by the licensee at the time of true up along with its carrying cost.
- 93.12 The distribution licensee shall submit such details, in the stipulated formats, of the variation between expenses incurred and the fuel and power purchase adjustment surcharge recovered, and the detailed computations and supporting documents, as required by the Commission, during true up of the normal tariff.
- 93.13 To ensure smooth implementation of the fuel and power purchase adjustment surcharge mechanism and its recovery, the distribution licensee shall ensure that the licensee billing system is updated to take this into account and a unified billing system shall be implemented to ensure that there is a uniform billing system irrespective of the billing and metering vendor through interoperability or use of open source software as available.
- 93.14 The licensee shall publish all details including the fuel and power purchase adjustment surcharge formula, calculation of monthly fuel and power purchase adjustment surcharge and recovery of fuel and power purchase adjustment surcharge on its website and archive the same through a dedicated web address.

93.15 Computation of Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge:

Formula:

$$\text{Monthly FPPAS for nth Month (\%)} = \frac{(A-B)*C + (D-E)}{\{Z * (1 - \text{Distribution losses in \%}/100)\} * \text{ABR}}$$

Where, (N+2)th month means the month in which billing of fuel and power purchase adjustment surcharge component is done. This fuel and power purchase adjustment surcharge is due to changes in tariff for the power supplied in (n)th month

A is Total units procured in (n)th Month (in kWh) from all Sources including Long-term, Medium –term and Short-term Power purchases (To be taken from the bills issued to distribution licensees)

B is bulk sale(inter-state sale) of power from all Sources in (n)th Month. (in kWh) = (to be taken from provisional accounts to be issued by State Load Dispatch Centre by the 10th day of each month and made available on SLDC website).

C is incremental Average Power Purchase Cost= Actual average Power Purchase Cost (PPC) including water charges, statutory taxes, duties and cess actually paid, from all Sources in (n) month (Rs./ kWh) (computed) - Projected average Power Purchase Cost (PPC) from all Sources (Rs./ kWh)- (from tariff order)

D Actual inter-state and intra-state Transmission Charges in the (n)th Month, (From the bills by Transcos to Discom) (in Rs)

E Base Cost of Transmission Charges for (n)th Month = (Approved Transmission Charges/12) (in Rs)

Z [{Actual Power purchased from all the sources outside the State in (n)th Month (in kWh)* (1 – Interstate transmission losses in % /100) + Power purchased from all the sources within the State(in kWh)– B}*(1 – Intra state losses in %)]/100 in kWh

ABR Average Billing Rate for the year for the year (to be taken from the Tariff Order in Rs/kWh);

Distribution Losses (in %) = Target Distribution Losses (from Tariff Order)

Intra-state Losses (in %) = As per Tariff Order

93.16 The Power Purchase Cost shall exclude any charges on account of Deviation Settlement Mechanism.

93.17 Other charges which include Ancillary Services and Security Constrained Economic Despatch shall not be included in Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge and adjusted through the true-up approved by the State Commission.

By order of the Commission

Sd/-

(Sudhir Kumar Kale)
Deputy Secretary.